International Journal of Applied Research 2018; 4(1): 167-170

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2018; 4(1): 167-170
www.allresearchjournal.com
Received: 21-11-2017
Accepted: 22-12-2017

डॉ0 संजू यादव
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, एम0 एल0 एस0 कॉलेज, सरिसब–पाही, मधुबनी, बिहार, भारत

Correspondence
डॉ0 संजू यादव
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, एम0 एल0 एस0 कॉलेज, सरिसब–पाही, मधुबनी, बिहार, भारत

बिहार की राजनीति में जाति गणना आधारित वोट की रणनीतिः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ0 संजू यादव

सारांश
बिहार चुनाव में जाति एक महत्वपूर्ण कारक है, और यह सभी का पर्याय है। यह एक मुश्किल सवाल है जो पूछा जा सकता है। लेकिन यह जवाब देना बहुत आसान है कि ये चीजें हर व्यक्ति के जीवन में होती हैं। हम बेटी देते हैं और अपनी ही जाति को वोट देते हैं। इसका मतलब है कि बिहार में वोट को जाति से अलग नहीं किया जा सकता था। जातिगत विशेषता, भूमिका, संख्या आदि के अनुसार उठाए गए प्रत्येक कदम ने 2015 के बिहार विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पत्र के माध्यम बिहार की राजनीति में जाति की गणना के आधार वोट की रणनीति को उजागर करने का प्रयास किया गया है।

कुट शब्दः डी.एन.ए., जे.डी.(यू.), आर.जे.डी., ओ.बी.सी., एस.सी., यादव, जाट, गुज्जर, अहीर

प्रस्तावना
बिहार 2015 के विधानसभा चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 66826658 थी जिसमें 35646870 पुरुष, 31177619 महिला और 2169 तृतीय लिंग शामिल हैं। हालांकि मतदाताओं को जाति, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन जाति के विचार का मुख्य महत्व है। अगड़ी जाति का अर्थ है ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ। भूमि और अन्य संसाधन जैसे कि आधिकारिक स्थिति, साक्षरता, बेहतर आर्थिक स्थिति और सामाजिक सम्मान इन जातियों का विशेषाधिकार हैं जो इन जातियों के राजनीतिक प्रभुत्व के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन अब स्थिति बदलने लगी है और इन जातियों को धीरे–धीरे राजनीतिक रूप से ग्रहण किया जा रहा है। हालांकि वे अभी भी अपनी संख्यात्मक शक्ति के लिए एक राजनीतिक महत्व को बनाए रखते हैं।
निश्चित रूप से यह 2015 के विधानसभा चुनावों में लालू, नीतीश और कांग्रेस द्वारा मिलकर तैयार किए गए दुर्जेय सामाजिक संयोजन के बारे में पता था और रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ अपने स्वयं के सामाजिक अंकगणित पर काम किया था। बिहार एक महाकाव्य राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार दिख रहा है, जो उन लोगों के महत्वपूर्ण सवाल पूछेगाः मोदी अपने पुराने जादू को बरकरार रखेंगे, क्या जनता लालू के साथ नीतीश को स्वीकार करेगी, क्या यह विकास की लड़ाई होगी या क्या बिहार में जाति काम पर होगी जो अब तक हमेशा जाति द्वारा मतदान करती थी। 2015 का विधानसभा चुनाव मूल रूप से बिहार में जातिगत संयोजन के आधार पर लड़ा गया था। इसकी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण से हुई है, पीएम मोदी की जुबान की एक पर्ची – कि नीतीश के डीएनए में कुछ गड़बड़ थी – ने नीतीश को अपनी पहली बड़ी शुरुआत दी। भले ही पीएम ने इसे सही किया, लेकिन नीतीश ने इसे बिहार के गौरव से जोड़ा और अपने भाषणों में इसे बजाया।
दूसरी बात यह है कि पीएम मोदी ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की है, नीतीश ने आंकड़ों के साथ काउंटर किया। यह विकास की राजनीति थी। मोदी ने अपने नौकरशाहों और डेटा टीम को नीतीश के डेटा का मुकाबला करने और अपने पॉज़र्स के लिए गोला–बारूद उपलब्ध कराने के लिए अगस्त और सितंबर की शुरुआत तक व्यस्त रखा। नीतीश ने सावधानीपूर्वक काम किया कि कैसे 1.25 लाख करोड़ रुपये के विशेष पैकेज में 1.08 लाख करोड़ रुपये पुराने और असंगठित परियोजनाओं के संकलन थे। वह बिहार के लिए अपने सात प्रस्तावों के साथ यह कहते हुए निकले कि राज्य अपना ध्यान रख सकता है। संघीय ढांचे पर जिबिस और काउंटर जिब थे। नीतीश पीएम की तुलना में आंकड़ों के साथ बेहतर तरीके से तैयार दिखे। इस बीच, लालू प्रसाद अपने भाषणों के एजेंडे के साथ संघर्ष कर रहे थे। वह जो सबसे अच्छा काम कर सकता था, वह यह मांग करना था कि केंद्र जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करे – लेकिन विकास की राजनीति ने ऊपरी हाथ को बनाए रखा।

एक अन्य विकास में, आरएसएस प्रमुख मोहन

आरक्षण नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता पर भागवत के बयान ने पाठ्यक्रम और चुनाव के खाके को बदल दियाः यह विकास–केंद्रित चुनाव से जाति चुनाव तक चला गया। एक महीने के लिए बिहार से मोदी की अनुपस्थिति, उनकी स्पष्ट स्पष्टीकरण भागवत की टिप्पणी, दादरी की घटना और 'उमंज हंअम विवाद ने नीतीश और लालू को वे उद्घाटन दिए, जिनकी उन्होंने तलाश की थी। अब उन्होंने घोषणा की कि भाजपा आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। भाजपा अनभिज्ञ थी।

मोदी ने नीतीश, लालू और कांग्रेस पर दलितों और ओबीसी के आरक्षण कोटे को हटाकर दूसरे समुदाय को देने का आरोप लगाते हुए अपना अंतिम फैसला सुनाया। ग्रांड एलायंस ने एक स्पष्ट स्पष्टीकरण दिया। बीजेपी ने आरक्षण के विज्ञापनों को प्रकाशित करने के लिए दबाव बनाया, जो कि ईसीपीएम द्वारा अपने आरक्षण पर विरोधियों को चुप कराने के लिए पीठ पर थपथपाया गया। उनका अंतिम पंच यह आरोप था कि नीतीश और लालू आतंकवादियों को ंस असुरक्षित कर रहे थे। हालांकि, नीतीश अस्वस्थ थे और अपने खाके से चिपके हुए थे – उनका रिकॉर्ड और लोगों की सद्भावना।

प्रो. दीपंकर गुप्ता, बिहार चुनाव प्रथम के अवलोकन के अनुसार, संख्याओं के आधार पर, कोई भी जाति अकेले अपने बल पर चुनाव नहीं जीत सकती है। उदाहरण के लिए यादवों के वर्चस्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों में भी, उस क्षेत्र की जनसंख्या में यादवों का प्रतिशत लगभग 15 प्रतिशत होगा। फिर से, बिहार की केवल 15 फीसदी आबादी में यादव शामिल हैं। तो अगर बिहार के 25 फीसदी विधायक यादव हैं, तो शेष हैं 75 फीसदी गैर–यादव हैं। कई यादवों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर लड़े, अन्य ने महागठबंधन पर। कुछ जीते, कुछ हारे। मुद्दा यह है कि जाति अकेले चुनाव नहीं जीतती है। लेकिन हम पाते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), उच्च जातियों और दलितों को एक साथ मिला, इस फैसले के बारे में लाने के लिए, अत्यंत पिछड़े वर्गों के कुछ वर्गों को छोड़कर। संयोग से, जाति क्रम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस तरह के सहवास को बढ़ावा देता हो।

यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम जाति व्यवस्था को पारस्परिक प्रतिकर्षण के रूप में परिभाषित करते हैं। इसलिए यदि वे एक साथ आते हैं, तो यह जाति के कारण नहीं हो सकता है; यह कुछ और होना चाहिए। मंडल कमीशन आंदोलन के दौरान, ओबीसी अपने मतभेदों की परवाह किए बिना एक साथ आए, क्योंकि उन्होंने भविष्य के वादे को देखा, जहां उनके बच्चे, जो कृषि या निम्न मध्यम वर्ग की पृष्ठभूमि के थे, कॉलेजों और सरकारी नौकरियों में पैर जमाने होंगे। इसलिए जाटों, गुर्जरों, अहीरों, कुर्मियों, यादवसेटक को शहरी क्षेत्रों में नौकरियों और शैक्षिक अवसरों के वादे के कारण एक साथ मिला।

हमने देखा कि बड़े पैमाने पर, कुश्वाह ने यादवों को वोट नहीं दिया और अनुसूचित जातियों ने पासवानों के साथ गठबंधन नहीं किया। इसलिए अगर आप अकेले जातिगत तर्क को देखते हैं, तो यह काम नहीं करेगा। जब वे एक साथ आते हैं तो यह जाति की आत्मीयता के कारण नहीं, बल्कि बाहरी कारकों के कारण होता है।

बिहार में जातिवाद का शुरुआती अनुभव

बिहार में पिछले अनुभवों का कहना है कि विभिन्न चुनावों में, विभिन्न प्रकार के कारकों ने काम किया था, लेकिन हर कदम पर लोगों को एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लोगों और लोगों के आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1977 और 1980 के दशक के दौरान कायस्थ ने राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। के। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल कायस्थ ही उनके लिए मतदान कर रहे थे क्योंकि अन्य जातियों ने भी उन्हें वोट दिया है और उस समय पार्टी लाइन के साथ–साथ नेताओं का व्यक्तिगत व्यक्तित्व महत्वपूर्ण था। लेकिन यह समुदाय हिंसा और राजनीति के बीच घनिष्ठ संबंध के कारण हाशिए पर चला गया और इस जाति के अधिकांश लोग सेवा उन्मुख थे, इसलिए वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट होने लगे। उसी समय ब्राह्मण समुदाय भी दो प्रमुख समूहों मैथिली और गैर मैथिली में राजनीति में प्रमुख था। मैथिल आमतौर पर उत्तरी जिलों जैसे दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर और बेगूसराय से आते हैं जबकि गैर मैथिल राज्य के अन्य हिस्सों में रहते हैं और आम तौर पर मध्य बिहार में केंद्रित होते हैं। कुछ प्रमुख नेता केदारपांडे, रामानंद तिवारी, जगनारायण त्रिवेदी, बिंदेश्वरी दुबे, के के तिवारी और लाल मुनि चौबे राजनीति में उभरे लेकिन वे बिहार स्तर की राजनीति के ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को सुनिश्चित नहीं कर सके। 1961 में जब बिनोदानंद झा मुख्यमंत्री बने और 1963 तक जारी रहे, तब मैथिली ब्राह्मण सामने आए। उस समय ब्राह्मण एकता में आ गए, लेकिन यह जारी नहीं रह सका। 1980 के दशक में प्रमुख राजपूत नेता जो महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे, वे थे सूरजनारायण सिंह, चंद्र शेखर सिंह, राम दुलारी सिन्हा, भीष्मनारायण सिंह। साथ ही राज्य में कांग्रेस पार्टी को असंतुष्ट समूहों की समस्या का सामना करना पड़ा। और यह बिहार में सवर्णों की महत्वपूर्ण भूमिका का अंत था और 1990 के दशक में दूसरे समूह ने उन्हें राजनीतिक मंच पर बहुत ही निर्णायक तरीके से उजागर किया था। 1967 में, एक गैर–कांग्रेसी सरकार– व्ठब् के बढ़ते राजनीतिक दबदबे से प्रेरित होकर पहली बार बिहार की सत्ता में आई। वास्तव में, ओबीसी राज्य के विधायकों के अनुपात में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 1969 (6) में लगभग 30 प्रतिशत थी। हालांकि, स्पष्ट शासी प्रमुखताओं की कमी के कारण कई दशकों की राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई। यद्यपि कांग्रेस की चमक बुरी तरह से धूमिल हो गई थी, दिल्ली में सत्ता पर उसकी लगातार पकड़ और विपक्ष के विखंडन की गहराई ने इसे 1989 तक राज्य में ऊपरी हाथ बनाए रखने की अनुमति दी थी। जनता दल, एक अग्रदूत 1990 में जनता दल जैसे पिछड़ी जाति के दलों के एक मेजबान ने एक चतुर राजनेता, लालू प्रसाद यादव, जो भारत में कई पिछड़े–जाति के नेताओं में से एक थे, ने सरकारी आयोग से एक सिविल कमीशन और शैक्षिक कोटा की वकालत करने के लिए सत्ता हासिल की। ओबीसी के लिए, परिणामी उच्च जाति के बैकलैश का उल्लेख नहीं करना चाहिए। इन फिजूलखर्ची को उजागर करते हुए, यादव ने डेढ़ दशक तक राजनीतिक सत्ता बनाए रखने के लिए पिछड़ी जातियों और मुसलमानों के एक साथ गठबंधन किया। यादवों के मूल राजनीतिक आधार में उनके अपने यादव समुदाय, ओबीसी के सबसे राजनीतिक और आर्थिक रूप से सफल उपसमूह शामिल थे। 1989 में राष्ट्रीय मंच पर अपनी जीत के दम पर 1990 में जनता दल सत्ता में आया।

जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और चंद्रशेखर और एस एन सिन्हा जैसे प्रसिद्ध पार्टी नेताओं के करीबी राम सुंदर दास के खिलाफ मामूली अंतर से विधायक दल के नेतृत्व की जीत के बाद लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। बाद में, लालू प्रसाद यादव ने लोकप्रिय और लोकलुभावन उपायों की एक श्रृंखला के माध्यम से जनता के साथ लोकप्रियता हासिल की। समाजवादी, नीतीश कुमार शामिल थे, धीरे–धीरे उन्हें छोड़ दिया और लालू प्रसाद यादव 1995 तक मुख्यमंत्री और साथ ही उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध राजा थे। वह एक करिश्माई नेता थे जिन्हें लोगों का समर्थन प्राप्त था और बिहार को लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री के रूप में ऐसा व्यक्ति मिला था। लेकिन वह राज्य के विकास की पटरी से उतरी वैगन को पटरी पर नहीं ला सके।

जब भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर हो गए, तो उन्होंने सीएम का पद छोड़ दिया लेकिन अपनी पत्नी का सीएम के रूप में अभिषेक

किया और प्रॉक्सी के माध्यम से शासन किया। इस अवधि में, प्रशासन तेजी से बिगड़ गया। इस समय के दौरान बिहार में यादव जाति राजनीतिक ऊंचाई पर उभरी थी और राज्य की सभी मशीनरी को नियंत्रित करना शुरू कर दिया था, उन्होंने लगभग सभी राजनीतिक पदों को अपने नियंत्रण में कर लिया था। 2004 में, लालू की जीत के 14 साल बाद, द इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने कहा कि "बिहार (भारत के सबसे खराब, व्यापक और अपरिहार्य गरीबी, भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के माफिया–डॉन्स से अप्रभेद्य हैं, जो जाति–आधारित सामाजिक व्यवस्था का संरक्षण करते हैं। जिसने सबसे बुरी सामंती क्रूरताओं को बरकरार रखा है।' 2005 में, विश्व बैंक का मानना था कि "निरंतर गरीबी, जटिल सामाजिक स्तरीकरण, असंतोषजनक बुनियादी ढांचे और कमजोर शासन" के कारण राज्य द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे बहुत थे। 2005 तक, राजद सरकार की लोकप्रियता में तेजी से गिरावट आई थी, जो राज्य की राजनीति के चौथे चरण की शुरुआत थी। पार्टी के पंद्रह साल के शासन में विकास की गति में गिरावट और धीमी गति से विकास और कानून–व्यवस्था में गिरावट की विशेषता देखी गई।

2005 के चुनाव में बिहार की इस स्थिति के कारण नीतीशकुमार बिहार के विकास के नारे के साथ आए। 2005 में, जैसे ही जनता के बीच एक असभ्यता पहुंची, मध्यम वर्ग में राजद को वोट दिया गया और लालू प्रसाद यादव अपने पूर्व सहयोगी और अब प्रतिद्वंद्वी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले गठबंधन से चुनाव हार गए। नीतीश कुमार ने बिहार की असली पहचान हासिल की है, जो कि वह जगह है जहाँ से दुनिया बदलने वाले लोग आते हैं जैसे गौतम बुद्ध या अशोक या शेरशाह सूरी या सिख गुरु। आर्थिक रूप से समृद्ध झारखंड के अलग होने के बावजूद, बिहार ने हाल के वर्षों में अधिक सकारात्मक विकास देखा है।

बीजेपी–जेडी (यू) गठबंधन ने एक शक्तिशाली राजनीतिक गठबंधन बनाया, जिसने हिंदू उच्च जातियों और जेडी (यू) के निर्वाचन क्षेत्र में ओबीसी के निचले पायदानों से बने बीजेपी की लोकप्रियता का फायदा उठाया, जिसे एक नया समूह कहा जाने लगा। अत्यंत पिछड़ी जातियों (ईबीसी) के रूप में पहचान का निर्माण राजद से गैर–यादव पिछड़ी जातियों के वोटों को छीनने का एक बड़ा प्रयास था। कुमार के जद (यू) ने भी बिहार के दलितों के वोट को फिर से अपने बीच सबसे अधिक पिछड़ा वर्ग का लक्ष्य बनाकर, एक नए महादलित श्रेणी के फैशन और इस नए समूह के कल्याणकारी लाभों को निर्देशित किया।

जाति कारक ने 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की ताजपोशी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें अगड़ी जातियों, गैर–यादव पिछड़े वर्ग और दलितों से समर्थन मिला। लालू के बाद और राबड़ी के शासन में, पहली बार बिहार के लोगों को विकास का स्वाद मिला। यह नीतीश कुमार का विकास मंत्र था जो राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के परंपरागत वोट बैंक में बदल गया था। लेकिन नीतीश ने चरम पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर शानदार सोशल इंजीनियरिंग की मिसाल कायम की, जिससे ओबीसी वर्ग में और विभाजन हुआ। नीतीश ने तब उन्हें भी विभाजित करके दलित को अपने खेमे में ले लिया। उन्होंने दलितों से महादलित नामक एक नई श्रेणी बनाई। इसलिए मुख्यमंत्री शिप कुमार ने अपने कार्यकाल में ओबीसी को कई समूहों और उप समूहों में विभाजित किया। नीतीश कुमार की ओर राजद के समर्थन से सच समूहों को अलग कर दिया गया है। वह बात 2009 के विधनसभा चुनाव तक जारी रही, जिसमें परिणाम सामने आया है और ओबीसी और उच्च जाति समूह के एक बड़े वर्ग ने जदयू के पक्ष में मतदान किया है। भाजपा गठबंधन और नीतीश भारी बहुमत के साथ सत्ता में आए। इस स्थिति में मूल रूप से ओबीसी वोट बैंक नितीश और उनके सोशल इंजीनियरिंग कार्यों की ओर स्थानांतरित हो गया।

फिर से 2015 के विधानसभा चुनाव के परिदृश्य को बदल दिया गया है, बिहार में विभिन्न जाति समुदायों को राज्य विधानसभा चुनावों से पहले दो बड़े गठबंधनों में से एक के खिलाफ या ध्रुवीकरण किया गया लगता है; हालांकि, यह सबसे पिछड़ी जाति के मतदाता हैं, जिन्हें मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के रूप में जाना जाता है, जो चुनाव के नतीजे तय कर सकते हैं।

पिछड़ी जातियों के मतदाता बड़ी संख्या में हैं। विभिन्न अनुमानों ने अलग–अलग संख्याएँ फेंक दीं, लेकिन आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि वे राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 25 प्रतिशत हैं। हालांकि अन्य जातियों के सदस्यों ने हाल के दिनों में अपनी पसंद की पार्टी के लिए एन–ब्लॉक का वोट दिया है, लेकिन निचले ओबीसी के वोट विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच बंटे हुए हैं। अन्य विचारों के अलावा, इसका मुख्य कारण इस श्रेणी के भीतर कई जातियां हैं। वे दूसरों में हैं, लोहार, कुम्हार, बुराड़ी, सुनार, ततवा, तेली, कहार और केवट। इन समुदायों के सदस्य लोगों को पारंपरिक सेवाएं प्रदान करते हैं।

पिछले कुछ चुनावों में वोटिंग पैटर्न के आधार पर, यह साबित हुआ कि व्यक्तिगत जातियों ने बड़ी संख्या में अपनी पसंद की पार्टियों को वोट दिया है। हालांकि यादवों ने बड़ी संख्या में लालू के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को वोट दिया है, कुर्मी ने बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल (यूनाइटेड) को वोट दिया है। इस तथ्य के बारे में कुछ भी छिपा नहीं है कि उच्च जाति के मतदाता पिछले दो दशकों से लगातार भाजपा के साथ हैं। हालांकि, उनमें से एक बड़ी संख्या ने पहले कांग्रेस को वोट दिया।

रामविलास पासवान अभी भी दलितों के बीच सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं, पासवानों के बीच, और वह इस समर्थन को उधार देने की क्षमता रखते हैं कि वह जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि पासवान अपनी पसंद की पार्टियों के साथ गठबंधन बनाने का प्रबंधन दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से करते हैं। लोजपा के आकार की किसी भी पार्टी के लिए, पासवान किसी भी अन्य नेता की तुलना में अधिक समय तक सत्ता में बने रहने मंक कामयाब रहे हैं। किसी जाति विशेष के मतदाताओं का किसी पार्टी के लिए बड़ी संख्या में मतदान का कारण मुख्य रूप से उस जाति से आने वाला नेतृत्व है। निचले ओबीसी मतदाताओं के बीच नेतृत्व की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप उनके वोट विभिन्न दलों के बीच विभाजित हो गए। वोटों का विभाजन भी हुआ क्योंकि उन्होंने ज्यादातर स्थानीय विचारों पर मतदान किया।

उपेंद्रकुशवाहा के साथ, भाजपा मतदाताओं को उस जाति के बारे में याद दिला रही है जिसमें प्रधानमंत्री जाति (निम्न ओबीसी) से है, और कुछ चतुर टिकट वितरण (निचले ओबीसी उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व देते हुए), ऐसा लगता है, भाजपा एक कोने में है। आगामी विधानसभा चुनाव में इन वोटों का बड़ा हिस्सा निचले ओबीसी को हमेशा उम्मीद थी कि सत्ता उनके लाभ के लिए विकेंद्रीकृत हो जाएगी और उनके साथ छल करेगी। आशा कम से कम कुछ वर्षों तक जीवित रही। परिवर्तन के संभावित एजेंट के रूप में भाजपा के साथ संभावना फिर से जीवित हो गई है। राय और आकांक्षाओं और मतों को जुटाने में आशाओं, आकांक्षाओं और धारणा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह देखा जाना बाकी है कि कौन सी पार्टी इसका सबसे अच्छा प्रबंधन करती है। एक अन्य कारक जो बिहार की राजनीति में प्रभावी रूप से काम करता है, वह है जनसांख्यिकी बदलाव जो ताजा अनिश्चितता का परिचय देते हैं। परंपरागत रूप से, बिहार में पुरुषों को महिलाओं की तुलना में मतदान करने की काफी अधिक संभावना है।

निष्कर्ष

विभिन्न विधानसभा और लोकसभा चुनावों से संकेत मिलता है कि निचले ओबीसी के वोट राजद और जद (यू) –बीजेपी गठबंधन के बीच 2005 के चुनावों तक विभाजित रहे। 2009 के लोकसभा चुनावों के बाद ही हम वरीयता में स्पष्ट बदलाव देख रहे हैं। उन्होंने पिछले कुछ दशकों में किसी भी चुनाव की तुलना में बड़ी संख्या में जद (यू) –बीजेपी गठबंधन को वोट दिया। 2010 के विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान इस बदलाव को और समेकित किया गया। 1996 से 2010 तक, जब जद (यू) और भाजपा गठबंधन में थे, तो एक चमत्कार यह था कि निचले ओबीसी ने जद (यू) या भाजपा को वोट दिया। 2014 के सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि बीजेपी की ओर एक बड़ी पारी का संकेत मिलता है जब पार्टी का जेडी (यू) के साथ कोई गठबंधन नहीं था – पार्टी का स्पष्ट संकेत मतदाताओं की इस श्रेणी के बीच अधिक लोकप्रिय है। ऐसे संकेत भी हैं कि भाजपा ने कम ओबीसी मतदाताओं के संबंध में जेडी (यू) के साथ अपने गठबंधन से लाभ उठाया, क्योंकि उनमें से बड़ी संख्या में भाजपा की तुलना में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडी (यू) को अधिक पसंद किया गया। हालांकि, कोई भी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव नरेंद्रमोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता के कारण थे। कोई यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं कह सकता है कि क्या चीजें वहां खड़ी हैं जहां वे थे।

संदर्भ

1. भारत की जनगणना 2011 और चुनाव आयोग इंडिया रिपोर्ट 2015।
2. इंडियन एक्सप्रेस 4 नवंबर 2015।
3. इंडियन एक्सप्रेस 18 अगस्त 2015।
4. इंडिया टुडे 22 सितंबर 2015।
5. बिजनेस स्टैंडर्ड 14 नवंबर 2015।